



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 24 मई, 2005/3 ज्येष्ठ, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-9, 10 मई, 2005

संख्या पी०सी० एच०-एच० ए० (5) 22/96-8625-31.—यह कि जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा श्रीमती सुरक्षा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत, हडल, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को सरकारी धनराशि के दुरुपयोग में संलिप्त होने के आरोप में उनके कार्यालय आदेश संख्या पंच-के०जी०आर०-ई(4) 52/91-330-35, दिनांक 21-1-2004 द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत हडल के पद से निलम्बित किया गया था ;

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 116 के अन्तर्गत तहसीलदार नूरपुर, जिला कांगड़ा को उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पंच-के०जी०आर०-ई(15) 8/91-1111-15, दिनांक 2-9-2004 को नियमित जांच सौंपी गई थी ;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का अध्ययन करने के उपरान्त जो आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध पाए गए, उनका विवरण निम्न है :-

क्र० सं०	निर्माण कार्य का नाम अथवा प्रयोजन	प्रधान द्वारा व्यय की गई राशि/अग्रिम प्राप्त राशि	कार्य की प्रगति अथवा स्थिति
1.	निर्माण रास्ता स्कूल से मान सिंह (मैरा)।	8,001/- ₹0	स्वीकृत स्कीम में परिवर्तन कर स्वेच्छा से निर्माण कार्य मान सिंह के घर से किया गया।
2.	—	12,160/- ₹0	बिना प्रयोजन 80 बैग सिमेंट का झूठा व्यय दिखा कर मु० 12,160/- ₹0 की धनराशि का छलहरण किया।
3.	मुरम्मत रास्ते	10,000/- ₹0	बजट प्रावधान के विपरीत स्वेच्छा से नया रास्ता कपाडी।
4.	सामुदायिक भवन हडल के लिए स्लैब डालने हेतु।	—	स्लैब डालने के लिए आवेक्षित निविदाएं आमन्त्रित न कर कार्य करवाया गया।
5.	अग्रिम राशि	1,00,000/- ₹0	दिनांक 24-1-2003 को मु० 1,00,000/- ₹0 अग्रिम राशि प्राप्त कर दिनांक 7-4-2003 तक समायोजन नहीं करके वापिस करना जो कि अस्थायी दुरुपयोग किया गया। मु० 2,400/- ₹0 ब्याज प्रधान से वसूली योग्य है।
6.	धन राशियों को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना।	—	प्रधान द्वारा मु० 4,280.74/- ₹0 दिनांक 1-5-2002 से 20-6-2002 तक मु० 2,005/- ₹0 दिनांक 22-6-2002 से 2-8-2002 तक मु० 2,980/- ₹0 दिनांक 3-5-2002 से 6-8-2002 तक तथा मु० 1,385/- ₹0 17-6-2002 तक अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर नियमों का उल्लंघन किया मु० 157/- ₹0 ब्याज प्रधान से वसूली योग्य है।
7.	मानदेय तकनीकी सहायक	4,000/- ₹0	3/2002 से 12/2002 तक मु० 4,000/- ₹0 मानदेय के रूप में तकनीकी सहायक को सभा निधि से अदायगी की गई। सभा निधि से तकनीकी सहायक को मानदेयकी अदायगी का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः यह कि जांच रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त श्रीमती सुरक्षा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत, हडल द्वारा अर्पनाई गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा कर्तव्य निर्वाहन में आपत्तिजनक कार्य क्लाप के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-3-2005 के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों ने उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाये तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया ;

अतः यह कि श्रीमती सुरक्षा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत, हडल द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर नथ्यों पर अधारित नहीं है। जिसके फलस्वरूप श्रीमती सुरक्षा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत हडल को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य क्लाप के फलस्वरूप दोषी पाए जाने के कारण उन्हें प्रधान पद से हटाया जाना उचित है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुरक्षा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत हडल, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है। तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित किया जाता है।

अधिसूचना

शिमला-9, 11 मई, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0-(3)-5/94-111-8704-09. क्योंकि ग्राम सभा, चनोग, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रस्ताव संख्या-9, दिनांक 4 अप्रैल, 2004 के अन्तर्गत ग्राम सभा चनोग के मुख्यावास को स्थान "सायरी" से बदलकर स्थान "पवाबो" स्थापित करने बारे निर्णय लिया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) के परन्तुक (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला शिमला के विकास खण्ड, मशोबरा की ग्राम सभा, "चनोग" के मुख्यावास को स्थान "पवाबो" में निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं तार्वजिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने और जिला शिमला के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझाव एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के सहर्ष आदेश देते हैं;

यदि ग्राम सभा, चनोग के मुख्यावास को स्थान "सायरी" से बदलकर स्थान "पवाबो" में निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हों तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, उपरोक्त ग्राम सभा, चनोग के मुख्यावास को निर्धारित करने वाले अंतिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त, शिमला की सिफारिशों के दृष्टिगत जारी करेगी।

कारण बताओ नोटिस

शिमला-9, 16 मई, 2005

संख्या पीसीएच-एच-ए (5) चूहन-8745-51.—यह कि श्रीमती श्यामा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत चूहन, को उपायुक्त चम्बा ने खण्ड विकास अधिकारी, मटियात द्वारा की गई प्रारम्भिक छानबीन के आधार पर ग्राम पंचायत कर्पेई के रास्ते का निर्माण स्विकृत स्थान पर न करवाने के आरोप में दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 को उनके पद से निलम्बित किया;

यह कि प्रधान द्वारा उपायुक्त द्वारा उपरोक्त निलम्बन आदेशों को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 148 के अन्तर्गत अपील की;

यह कि निदेशक महोदय द्वारा इन निलम्बन आदेशों को निलम्बन की पूर्ण प्रक्रिया न अपनाते तथा उपायुक्त, चम्बा को प्रतिवेदिका की सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथ्यों का परीक्षण करके मामले में कार्रवाई करने के आदेश देकर 25 जुलाई, 2004 को खारिज किया गया;

यह कि उपायुक्त चम्बा द्वारा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत तहसीलदार, डलहौजी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया;

जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त, चम्बा को 19 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत की तथा स्पष्ट किश कि जिला योजना अधिकारी चम्बा के पत्रांक 2002-2003, दिनांक 2-9-2003 के अनुसार ग्राम पंचायत चूहन, में कपई रास्ते के निर्माण हेतु मु० 30,000/- रुपये दिए गए। सहायक अभियन्ता व जिला योजना अधिकारी, चम्बा द्वारा रास्ते का मौका निरीक्षण 4-6-2004 को करने पर यह पाया गया कि कपई रास्ते के बजाए कम्बई ग्राम पंचायत, समलेऊ में रास्ता बनाया गया है। इसके अतिरिक्त रास्ते की लम्बाई 198.20 मीटर दर्शाई गई है जबकि मौके पर रास्ते की लम्बाई 123.20 मीटर है। अतः रास्ते की लम्बाई कम होने के कारण ग्राम पंचायत चूहन से मु० 7692/- रुपये की वसुली भी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तावित की गई।

जांच रिपोर्ट पर उपायुक्त, चम्बा को पुनः टिप्पणियां लेने उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि धन को स्वीकृति ग्राम पंचायत चूहन में कपई पक्का रास्ता के लिए की गई थी जबकि रास्ते का निर्माण अन्य साथ लगती पंचायत समलेऊ में करवाया गया। इस प्रकार प्रधान ने स्वीकृत धनराशि को ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार से बाहर व्यय कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इस प्रकार का दुरुपयोग उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। किसी कार्य के लिए स्वीकृत राशि का अन्य कार्य पर व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अतः प्रधान उपरोक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (ख) के अन्तर्गत अवचार की दोषी है।

अतः आगामी कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वह उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। उनका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसीलदार, डलहौजी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।